कृषि से जुड़े उद्योगों के विकास से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

दिनेश अबरोल
मुख्य विज्ञानी (से. नि.), सीएसआइआर-एनआइएसटीएडीएस

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारों को खेती के साथ इससे जुड़े उद्यमों के विकास पर फोकस करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण और मछली पालन के जरिये ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है।

ग्रामीण भारत की समृद्धि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी अब भी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट या दूसरी फैक्ट्रियां बहुत कम है। सरकार के प्रयासों के बावजूद आज भी ज्यादातर खेती पुराने तौर तरीकों से हो रही है। ऐसे में खेती से किसानों की आय घट रही है। 2002-03 में परिवार की कुल आय में खेती का योगदान 46 प्रतिशत था और 2018-19 में यह घट कर 36 प्रतिशत रह गया है। किसान परिवार की औसत मासिक आय सिर्फ 10,218 रुपये थी। गिरती आय और बढ़ता कर्ज कृषि पर निर्भर परिवारों के हालत खुद बयान कर रहा है। भारत की करीब 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है और वह रोज 2400 से कम कैलोरी ले रही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 1,37,757 करोड़ रुपये (केंद्रीय बजट का 2.7%) आवंटित किया। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2.5 प्रतिशत कम है। पीएम-किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि में लचीलापन नहीं आएगा। इन प्रणालियों के लिए सरकार को सहफसली खेती, पशुपालन, कृषि, मृदा और जल प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण को बढ़ावा देने के साथ थोक व गैर-थोक कृषि उपज के लिए सार्वजनिक बाजारों के एकीकरण की नीति अपनानी होगी और किसानों को तकनीकी सहायता मुहैया करानी होगी। कैश ट्रांसफर की नीतियों से कृषि क्षेत्र को बहुत मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। सार्वजनिक निवेश से कृषि आवंटन में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। लाभार्थी-आधारित योजनाएं आवंटन का पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा हैं। व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख आवंटन का एक उत्कृष्ट उदाहरण पीएम-किसान के तहत किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये दिया जाना है। लेकिन इससे किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया हो, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एकीकृत खेती के माडल पर जोर देने की जरूरत है। इस माडल में फसल उगाने के साथ पशुपालन, मछली पालन और वानिकी के जरिये किसानों और श्रमिकों को वर्ष भर लगातार आय मुहैया कराई जा सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च (आइएफएसआर) मोदीपुरम ने एकीकृत खेती का माडल विकसित किया है। पूरे देश में इसे अपनाया जा सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिल कर काम करना होगा। तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण और खेती से जुड़े दूसरे उद्यम लगा कर ही ग्रामीणों की आय को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन और मछली पालन में ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए युवाओं को बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। आम तौर पर सरकारी बैंक एमबीए या तकनीकी पढ़ाई से जुड़ी डिग्री के बिना पशुपालन या मछली पालन के लिए युवाओं को लोन देने में आनाकानी करते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वरोजगार के लिए युवाओं को आसानी से लोन मिल सके। इसमें निहित जोखिम भी सरकार को उठाना होगा क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दोहरे अंक में पहुंचाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं है।